549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>प्रकरण क्रमांक 5974/2019 मेसर्स एकता ग्रेनाईट, श्री प्रदीप सिंह, मकान नं. 444, ग्राम ज्योराहा, तसहील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ग्रेनाईट स्टोन माइन, खसरा नं. 410, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,50,000 मी.^{3}, ग्राम चुरियारी तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । Env. Consultant Globus Environment Engineering Service, Lucknow (U.P.)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 410, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम चुरियारी तहसील गौरीहार जिला छतरपुर म.प्र. पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 390वीं दिनांक 10/08/19 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ के ऊपर स्थित है जिसके पश्चिम दिशा में एक स्टोन क्रेशर कार्यरत है। खदान के उत्तर दिशा में लीज

बाउण्ड्री से लगी हुई एक कच्ची रोड़ है जो क्रेशर तक पहुॅच मार्ग है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी खदान कार्यरत न होने के कारण अभी यह कच्चा रोड़ उनकी लीज से सटकर निकल रहा है । जब उनकी खदान पर कार्य प्रारंभ होगा तो वह खदान के बाहर से अपना रास्ता बनाकर कार्य करेंगे । समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि चूॅकि वर्तमान परिस्थिति में कच्चा रोड़ विद्यमान है, अतः कच्चे रोड़ से 10 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाये । गूगल एमेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि लीज में कुछ पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि पूरा क्षेत्र फ्रेक्चर्ड रॉक से अच्छादित है तथा उनके बीच–बीच से झाड़िया उग आई हैं । वृक्ष प्रजाति के मात्र 02 पेड़ विद्यमान हैं, जिनको नहीं काटा जायेगा तथा उनके पास ही साइट आफिस व अन्य सुविधाओं का विकास किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि प्रोजेक्ट साइट की वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के बहुत करीब है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इसका मुख्य कारण खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित स्टोन क्रेशर है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपाय ।
- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना ।
- ✓ खदान के पूर्वी क्षेत्र में अतिरिक्त सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन कि खनिज परिवहन हेतु 40 टन क्षमता के ट्रक का उपयोग किया जावेगा, ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/0/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज का परिवहन 40 टन क्षमता के ट्रक से किया जावे ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।

3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 38.00 लाख एवं रिकरिग 03.16 लाख प्रति वर्ष ।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 3.16 लाख :–

Year	CER Activity	Total Cost (in Rupees)
1	Covid awarness program and disrtibution of mask, sanitizer and handwash.	66,000
2	Provision for food distribution in Anganwadi village Churyari for a year.	1,00,000
3	Renovation works in nearby school in Gaurihar (window panels /fencing /plastering and whitewashing/floor).	1,50,000
	Total CER Cost	**3,16,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 4800 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	2750
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, करंज, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। ट्री–गार्ड के साथ जैव विविधता का अध्ययन/वनस्पतिक/जीव जंतु, ट्री–गार्ड के साथ ।	1150
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
4	विद्यालय मे	करंज, कनक चंपा, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
		योग	4800

2. <u>प्रकरण कमांक 6512/2019 – मेसर्स एकता ग्रेनाईट, द्वारा 63, सनसिटी कालोनी, जिला छतरपुर (म.प्र.) ग्रेनाईट स्टोन माइन, खसरा नं. 410, रकबा 3.100 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,50,000 मी.^{3}, ग्राम चुरियारी तहसील गौरीहार जिला छतरपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 410, रकबा 3.100 हेक्टेयर, ग्राम चुरियारी तहसील गौरीहार जिला छतरपुर म.प्र. पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक कमांक 396वीं दिनांक 01/10/19 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ के ऊपर स्थित है जिसके पश्चिम दिशा में एक और खदान स्थित है जो इन्हीं परियोजना प्रस्तावक की है। खदान के पूर्वी दिशा में लीज के अंदर एक कच्ची रोड़ विद्यमान है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उनकी खदान कार्यरत न होने के कारण अभी यह कच्चा रोड़ उनकी लीज से निकल रही है जो पूर्व में आवंटित खदान मालिक द्वारा खानिज निकालने हेतु बनाई गई थी। जब उनकी खदान पर कार्य प्रारंभ होगा तो वह खदान के बाहर से अपना रास्ता बनाकर कार्य करेंगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र के अंदर दक्षिणी भाग में जो गढ्ढें दिख रहे है वह पूर्व में एक अन्य कम्पनी द्वारा वर्ष 2014–17 के दौरान किए गए माइन पिट है जिस हेतु उसको अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी । समिति ने इस स्थिति के अवलोकन से यह पाया कि पूर्व के परियोजना प्रस्तावक द्वारा अस्थाई अनुज्ञा के तहत् जो खनन् कार्य किये गये हैं उसके द्वौरान पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए कार्य (जैसे : वृक्षारोपण, फेंसिंग इत्यादि) वर्तमान स्थिति में परिलक्षित नहीं हो रहे है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा में 100 मीटर की दूरी एक छोटा तालाब विद्यमान है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि प्रोजेक्ट साइट की गई वायु गुणवत्ता मापन के परिणाम निर्धारित मानक सीमा के बहुत करीब है जिसके संदर्भ में पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इसका मुख्य कारण खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में स्थित स्टोन क्रेशर है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- ✓ वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपाय ।
- ✓ पुनरीक्षित जल खपत योजना ।
- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन कि खनिज परिवहन हेतु 40 टन क्षमता के ट्रक का उपयोग किया जावेगा, ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–2,50,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज का परिवहन 40 टन क्षमता के ट्रक से किया जावे ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 29.85 लाख एवं रिक्करिग 03.16 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में राशि रू. 4.60 लाख :–

	CER Activity	**Total Cost (in Rupees)**
1	Covid Awareness program and distribution of mask, sanitizer and handwash in nearby Villages	1,00,000
2	Provision for food distribution in Anganwadi village Churyari for a year.	1,00,000
3	Renovation work in nearby school in Gaurihar (window panels/fencing/plastering and whitewashing/floor)	2,60,000
	Total CER Cost	**4,60,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3700 नग वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1900
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, करंज, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ। जैव विविधता का अध्ययन/वनस्पतिक/जीव जंतु, ट्री–गार्ड के साथ ।	900
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, हर्रा, बहेडा, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
4	विद्यालय मे	करंज, कनक चंपा, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
		योग	**3700**

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

3. <u>प्रकरण क्रमांक 6717/2019 – श्रीमती संतो चौरसिया, ग्राम बिलौआ के पास, तहसील डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 3624/1, रकबा 1.214 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 30,000 मी.^{3}, ग्राम बिलौआ तहसील पिछोर जिला ग्वालियर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । Env. Consultant - Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल **खसरा नं.** 3624/1, रकबा 1.214 हेक्टेयर, ग्राम बिलौआ तहसील पिछोर जिला ग्वालियर म.प्र. पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 460वीं दिनांक 24/09/20 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 170 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर दिशा में 200 मीटर पर नहर एवं दक्षिण एवं पूर्व दिशा में 270 मीटर आबादी होना परिलक्षित होता है । पश्चिम दिशा में कच्चा रोड़ विद्यमान है, जिमके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह कच्चा रोड़ खदानों में आने–जाने हेतु उपयोग किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य जैसे : स्वास्थ्य शिविर, स्कूल मे कार्य, कोविड–19 के तहत् कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–30,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज का परिवहन 40 टन क्षमता के ट्रक से किया जावे ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 05.35 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 03.56 लाख प्रति वर्ष ।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.10 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Distribution of pen, pencil, Note book, Shoose & school uniform at Govt. School of Village Biloua.	50,000
2.	Medical health check up camp will be arranged at village Biloua.	50, 000
3.	Distribution of food & Snacks to Aanganwadi center of Biloua Village.	1,00,000
4.	Distribution of Covid -19 test kits, sanitizers, masks etc. at village Biloua.	10,000
	Total	**2,10,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1450 नग वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	250
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदम, नीम, शीशम, करंज, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । ट्री–गार्ड के साथ जैव विविधता का अध्ययन/वनस्पतिक/जीव जंतु, ट्री–गार्ड के साथ ।	600
3	स्कूल प्रांगण में	नीम, पीपल, मुनगा, पलास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	650
		योग	1450

4. <u>प्रकरण क्रमांक 8916/2022 – मेसर्स पी.डी. स्टोन, श्री विशाल पहवानी, 11 पैलेस कालोनी, जिला इंदौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 125/2/3, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10,527 मी.^{3}, ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इंदौर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 125/2/3, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम रंगवासा तहसील देपालपुर जिला इंदौर म.प्र. पर स्थित है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज

अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 2651 दिनांक 13/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 11.600 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर–पश्चिम दिशा में 240 मीटर पर आबादी और पश्चित् दिशा में 515 मीटर पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 84 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित होता है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के पश्चिम दिशा में 84 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खदान के उत्तर–पूर्वी दिशा में 240 मीटर दूरी पर आबादी है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

5. <u>प्रकरण क्रमांक 8963/2022 – मेसर्स न्यू जय दाऊबाबा स्टोन क्रेशर, श्री सरदार सिंह गुर्जर, पारस विहार कालोनी, झॉसी रोड़ थाना के सामने, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 2724/min-2, 2725,2729, 2730, 2728/ min-2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 60,00 मी.^{3}, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्। Env. Consultant - Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 2724/min-2, 2725,2729, 2730, 2728/ min-2, रकबा 2.603 हेक्टेयर, ग्राम बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर .प्र. पर स्थित है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा

पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 9888 दिनांक 03/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07. अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 13.907 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 165 मीटर पर आबादी और उत्तर दिशा में 180 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित होता है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण–पश्चिम दिशा में 60 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खदान के पश्चिम दिशा में 160 मीटर दूरी पर आबादी है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये तथा लगभग 40 मीटर का सेट–बैक प्रस्तावित किया जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

6. <u>प्रकरण क्रमांक 8929/2022 –श्री जीवन चौधरी, ग्राम खंडवा तहसील पीथमपुर जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 168/6, 168,7/1, 168/7/2, 168/11 पेकी रकबा 2.80 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–19000 मी.^{3}, वेस्ट – 1000 मी.^{3}, मुरूम एज ओव्हर –12,000 मी.^{3}, ग्राम कल्यांसीखेडी तहसील पीथमपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् । Env. Consultant - Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल **खसरा नं.** 168/6, 168,7/1, 168/7/2, 168/11 पेकी रकबा 2.80 हेक्टेयर, ग्राम कल्यांसीखेडी तहसील पीथमपुर जिला धार .प्र. पर स्थित है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि

कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3484 दिनांक 30/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 11.80 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 20 मीटर पर कच्चा रोड़ होना परिलक्षित होता है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण दिशा में 20 मीटर दूरी पर कच्चा रोड़ है, जिसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

7. <u>प्रकरण क्रमांक 6735 – श्री मनोज कुमार सिंह, निवासी 8 बी/के.के. 25, कृष्णापुरम, देवनगर जिला आगरा उ.प्र. । स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 523 रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता विस्तार 25000 मी.^{3} से 1,10,000 मी.^{3}, ग्राम बिलहेरीकलांन तहसील दतिया जिला दतिया के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 523 रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम बिलहेरीकलांन तहसील दतिया जिला दतिया म.प्र. पर स्थित है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 454वीं . दिनांक 29/08/20 में टोर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 524वीं दिनांक 29/10/21 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा कुछ अतिरिक्त जानकारी व पुनरीक्षित फार्म–2 में निम्न जानकारी चाही गई थी :–

1. In point no.14.6- please justify, how post monsoon GW table be lower than the pre monsoon GWT.
2. In point no.15-0 permission for GW withdrawal are not uploaded.
3. In point no. 17- provide relevant information for solid waste generation/management.

4. In point no.18.1 NOX base line value 20.1and predicted incremental value 15.8 total value will be 35.9 define source of NOx , how?
5. In point no.30.1 justify 3542 water bodies in buffer area.
6. In point no.35.11- proposed depth of mine is 48 m and as per point 14.6 Ground water table is shown as 50 m elaborate protection measures.
7. In point no. 35. 38 valid consultant certificates shall be submitted.
8. Being case of expansion complete TOR point wise compliance report why not attached?
9. As per additional TOR point report of Tehsildar and mine water discharge plan shall be submitted.
10. Being case of expansion MoEF&CC compliance report shall be submitted from competent authority.
11. Being case of expansion no plantation is seen in the lease area thus minimum 500 plantations shall be carried out and credible proof shall be submitted for further consideration of this case.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है अतः प्रकरण पुनः समिति के समक्ष रखा गया।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी पालन प्रतिवेदन उनके द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6 माही पालन प्रतिवेदन एसईआईएए में प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन की फोटोप्रति संलग्न है । इसी प्रकार कार्यालय ग्राम पंचायत ने पत्र दिनांक 25/1/22 के माध्यम से सूचित किया है कि ग्राम पंचायत बिलहरी कलां के ग्राम गोपालपुरा में खसरा नं. 523 में जो खदान/लीज आंवटित की गई है उस खसरे में न कोई तालाब न कोई बाटर बाडी है न कोई पंचायत द्वारा बनाया गया जलाशय है, यह पूरा लीज एरिया है । परियेाजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया कि चारों ओर पहाड़ होने के कारण तथा यह हिस्सा तलहटी होने पर बरसात के पानी का संग्रहण होने के कारण वह तालाब जैसा प्रतीत होता है । वास्तविक में वह वाटर बॉडी नहीं है, प्रमाण के तौर पर ग्राम पंचायत का पत्र व फोटोग्राम प्रस्तुत कर रहे है । परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के पालन बावत् उनके द्वारा 500 वृक्षों (250 जामुन एवं 250 करंज) का वृक्षारोपण जनवरी, 2022 में कराया गया है, जिसके फोटोग्राफ संलग्न है । उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं

स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए निम्नानुसार अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–1,10,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. खनिज का परिवहन 40 टन क्षमता के ट्रक से किया जावे ताकि प्रतिदिन होने वाले फेरों की संख्या में कमी आवे ।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 11.55 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03.88 प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.20 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Distribution of pen, pencil, Note book, Shoose & school uniform at Govt. School of Village Bilherikalan.	50,000
2.	Medical health check up camp will be arranged at village Bilherikalan.	50, 000
3.	Distribution of food & Snacks to Aanganwadi center of Bilherikalan Village.	1,00,000
4.	Distribution of Covid -19 test kits, sanitizers, masks etc. at village Bilherikalan.	20,000
	Total	**2,20,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	जंगल जलेबी, करंज, नीम, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1400
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, जामुन, करंज, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	1000
		योग	2400

8. **<u>प्रकरण क्रमांक 8949/2022 –श्रीमती अंकिता सोनकर, 2390, सेठीनगर, कुम्हार मोहल्ला, रामपुर वार्ड, नं. 11, ग्वारीघाट जिला जबलपुर (म.प्र.) स्टोन/मुरूम क्वेरी, खसरा नं. 26 पार्ट, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–26,305 मी.^{3}, मुरूम – 3,467 मी.^{3}, ग्राम खुरशी तहसील एवं जिला जबलपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 26 पार्ट, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम खुरशी तहसील एवं जिला जबलपुर म.प्र. पर स्थित है ।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 3039 दिनांक 14/10/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 11.73 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 500 मीटर पर पक्का रोड़, दक्षिण दिशा में नहर 780 मीटर पर, पूर्व दिशा में 720 मीटर पर आबादी होना परिलक्षित होता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रकरण के दस्तावेजों के साथ डी.एस.आर. ऑन लाईन अपलोड नहीं की गई है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने अनुरोध किया कि वे इस क्षेत्र से संबंधित डी.एस.आर. की फोटोप्रति अभी प्रस्तुत कर रहे है । अतः उनके प्रकरण को टीओआर के लिए मान्य किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों की विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि क्षेत्र के पास वन क्षेत्र स्थित है, जिस संदर्भ में संभागायुक्त की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 01/09/18 के कार्यवाही विवरण के बिंदु क्रमांक–10 पर खदान संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है किंतु यह अनापत्ति श्री संजय तिवारी के नाम पर है तथा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 3098 दिनांक 22/10/21 के माध्यम से सदस्य सचिव, सिया/सेक को यह सूचित किया गया है कि –

''उपरोक्त विषयांतर्गत पट्टेदार श्रीमती अंकिता सोनकर पति श्री अखिल सोनकर पता 2390, सेठीनगर, कुम्हार मोहल्ला जिला जबलपुर के पक्ष में ग्राम खुर्सी तहसील जबलपुर खसरा नं. 26 रकबा 4.00 है. पर खनिज पत्थर (क्रेशर आधिारित) 10 उत्खनन् पट्टा हेतु पत्र क्रमांक 2698 दिनांक 07/09/21 से स्वीकृति आदेश जारी किया गया ।

यह कि श्रीमती अंकिता सोनकर के पक्ष में उत्खनन् पट्टा जारी करने हेतु मान्नीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित वन समिति की बैठक 01/09/18 में श्री संजय तिवारी पिता श्री भूप नारायण तिवारी, निवासी जबलपुर के पक्ष में जारी अनापत्ति को मान्य करते हुए उपरोक्त उत्खनन् पट्टा स्वीकृत किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि श्रीमती अंकिता सोनकर के पक्ष में स्वीकृत उत्खनन् पट्टा क्षेत्र ग्राम खुर्सी तहसील जबलपुर खसरा नं. 26 रकबा 4.00 हे. क्षेत्र एवं श्री संजय तिवारी के पक्ष में वन समिति की बैठक दिनांक 01/09/18 में जारी अनापत्ति बावत् क्षेत्र एक ही होने से वन समिति की बैठक दिनांक 01/09/18 में जारी अनापत्ति को मान्य करने का कष्ट करें ''।

समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि इस प्रकरण में सेक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से जानकारी की पुष्टि की जाये तथा समिति खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 3098 दिनांक 22/10/21 के आधार पर इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) से प्राप्त हुई है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनका क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये ।

9. <u>प्रकरण क्रमांक 8946/2022 – श्री शैलेन्द्र वर्मा, 205, कुनवी नगर, शांति मंदिर के पास जिला खण्डवा (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 410, रकबा 5.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–48,450 मी.^{3}, ग्राम रूंधी तहसील एवं जिला खण्डवा के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 410, रकबा 5.00 हेक्टेयर, ग्राम रूंधी तहसील एवं जिला खण्डवा म.प्र. पर स्थित है।

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 1110 दिनांक 15/12/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण दिशा में 140 मीटर पर सुखता नदी है तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर एच.टी. लाईन गुजर रही है । इसी प्रकार दक्षिण–पूर्वी दिशा में 170 मीटर एम.पी.ई.बी. का सब स्टेशन है जिस कारण उनके द्वारा 30 मीटर का सेट–बैक छोड़ दिया गया है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव को यह सलाह दी गई कि वे प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना में खमार व चिरौल प्रजाति के पेड़ों को भी शामिल करें तथा बैरियर जोन में प्रस्तावित वृक्षारोपण के कतारों के बीच में सीताफल के पेड़ भी लगाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/02/22 के द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं निम्न स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–48,450 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 12.35 लाख प्रतिवर्ष एवं रिकरिंग राशि रू. 01.32 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Distribution of pen, pencil, Note book, Shoose & school uniform at Govt. School of Village Biloua.	50,000
2.	Medical health check up camp will be arranged at village Biloua.	50, 000
3.	Distribution of food & Snacks to Aanganwadi center of Biloua Village.	1,00,000
4.	Distribution of Covid -19 test kits, sanitizers, masks etc. at village Biloua.	10,000
	Total	**2,10,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 6000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	महुआ, नीम, पीपल, बहेरा, खमार चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ । । (वृक्षारोपण की लाईनों के बीच में सीताफल के पौधें लगाये जायेंगे)	2800
2	परिवहन मार्ग एवं प्रस्तावित सेट बैक क्षेत्र में	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदम, आम, जामुन, कटंग बॉस, कटहल, कैथा, बेल, करंज, नीम खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	3200
		योग	6000

10. **<u>प्रकरण क्रमांक 8948/2022 – श्री रूपलाल कोल, ग्राम टीमर तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 142/5, रकबा 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–12,000 मी.^{3}, ग्राम अमझर तहसील कुंडम जिला जबलपुर के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 142/5, रकबा 1.60 हेक्टेयर, ग्राम अमझर तहसील कुंडम जिला जबलपुर म.प्र. पर स्थित है।

प्रकरण आज दिनांक 15/02/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा इस प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण अंतिम अवसर प्रदान करते हुए हेतु प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया तथा फिर भी यदि परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहता है तो यह प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा।

11. **<u>प्रकरण क्रमांक 8944/2022 – श्री उदयद दुबे, न्यू कटनी, पाठक वार्ड कालोनी, हरवारा जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 68, रकबा 2.30 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–60,000 मी.^{3}, ग्राम हरदुआ तहसील एवं जिला कटनी के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 68, रकबा 2.30 हेक्टेयर, ग्राम हरदुआ तहसील एवं जिला कटनी म.प्र. पर स्थित है।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की

एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 78 दिनांक 07/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.00 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के ऑन लाईन अपलोड अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण दिशा में 540 मीटर पर रेलवे लाईन, उत्तर/पूर्व में उद्योग 750 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में प्राकृतिक जल संरचना 120 मीटर पर होना परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ समिति के अनुशंसा अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर (स्कूल में हाई रिसॉल्यूशन माइक्रोस्कोप)।
- ✓ समिति के अनुशंसा अनुसार पुनरीक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/2/21 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–60,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 18.64 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01. 53 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	04 Computer systems with printers in Govt. School Village Hardua.	1,00,000
2.	Equipments for chemistry and physics lab in Govt High School	45,000
3.	Provide high resolution Microscope to Govt High School	55,000
	Total	**2,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 3000 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सिरस, रीठा, चिरोल, खम्हार, जंगल जलेबी, बैम्बू, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1800
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, खाखर, कचनार, करंज, कदंब, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	300
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, सीताफल, अमरूद, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
4	विद्यालय मे	करंज, कनक चंपा, अशोका, पुतरनजीवा, मौलश्री एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	400
		योग	3000

12. <u>प्रकरण क्रमांक 8960/2022 – मेसर्स श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कं., प्रो. फतेहपुरा रोड़ ज्योति सिनेमा के सामने, जिला शिवपुरी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 638 रकबा 1.450 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–9,000 मी.^{3}, ग्राम दरगवां तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 638 रकबा 1.450 हेक्टेयर, ग्राम दरगवां तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. पर स्थित है।

आज दिनांक 15/02/22 को परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन मैनेजमेंट योजना, पी.एफ.आर। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, एकल प्रमाण–पत्र (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 41 दिनांक 10/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 4.0 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के ऑन लाईन अपलोड अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 130 मीटर पर कच्चा रोड़, पश्चिम दिशा में कच्चा रोड़ 15 मीटर पर होना परिलक्षित हो रहा है । अतः प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति के अनुशंसा अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

✓ स्वाइल प्रोफाईल ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/02/2 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–9,000 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 6.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.94 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Construction of a Toilet in Primary School & distribution of 02 Black boards.	37,500
2.	Distribution of Covid -19 test kits, sanitizers, masks etc. at village Biloua.	2,500
	Total	**40,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 1800 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, सफेद कस्टार, करंज, आंवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1200
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, करंज, आवंला, महुआ, चिरोल, जंगल जलेबी, नीम, आम, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	200
3	मुक्ति धाम ग्राम– द्रगवान	पीपल, बरगद, नीम, आम, करंज, सिस्सू, आंवला, चिरोल अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
4	शा0. विद्यालय ग्राम– द्रगवान	पीपल, बरगद, नीम, करंज, सिस्सू, कचनार, चिरोल अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	100
		योग	1800

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

13. <u>प्रकरण क्रमांक 7686/2020 – मेसर्स तोमर बिल्डर एवं कांट्रेक्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 2, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–1,50,000 मी.^{3}, ग्राम मगरोनी तहसील बेराड़ जिला शिवपुरी के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम मगरोनी तहसील बेराड़ जिला शिवपुरी म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 528वी बैठक दिनांक 23/11/21 को प्रस्तुतीकरण दौरान चाही गई जानकारी आज दिनांक तक परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस प्रकरण में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओएम दिनांक 15/03/2021 के अनुसार 30 दिवस से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी न प्रस्तुत करने के कारण इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को भेजा जाना अनुशंसित है।

14. <u>प्रकरण क्रमांक 8832/2021 – श्रीमती सोनम जायसवाल, ग्राम बगवनिया तहसील देपालपुर जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 46/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–37,500 मी.^{3}, ग्राम भूडाल तहसील धरमपुर जिला धार के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 46/1पेकी, रकबा 2.00 हेक्टेयर, ग्राम भूडाल तहसील धरमपुर जिला धार म.प्र. पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 534वी बैठक दिनांक 15/12/21 को प्रस्तुतीकरण दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे :–

- PP shall be submitted photographs (with latitude & longitudes) with M.O. clarification w.r.t. human settlements in the North- East side.
- Justify 37,500 TPA wrt quantity mentioned in the form-II.
- Revised CER- Propose proposal of drinking water facility with submersible pump and over head tank and distribution of computer & printer in the village school. \

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्ततन मंत्रालय की परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की गई ।

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी का प्रस्तुतीकरण दिनांक 15/02/2 को समिति के समक्ष किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

✓ समिति के सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 15/02/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–37,500 मी.^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रू. 07.23 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.04 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.70 लाख :–

S. No.	Proposed activity	Annual recurring expenses in Rs.
1.	Distribution of Computer, Printer & Provision for drinking water facilities at Govt. School of Village Dhamnod.	90,000
2.	Medical health check up camp (Oral hygine, Diabetes & Blood Pressure) will be arranged at village Village Dhamnod.	90, 000
3.	Provision of Hand Pump for drinking water at Govt. School of Village Dhamnod.	90,000
	Total	**2,70,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार कम से कम 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, अशोक, कचनार, करंज, कदंब, अर्जुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	500
2	परिवहन मार्ग	कनक चंपा, पुत्ररनजीवा, मौलश्री, कदंब, आम, जामुन, अमरूद, सीताफल, नीबू, इमली एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, ट्री–गार्ड के साथ ।	400
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, सीताफल, अमरूद, मुनगा, जामुन, नीबू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ।	1500
		योग	2400

15. <u>Case No 8880/2021 M/s. Ipca Laboratories Ltd, Shri Manoj Kumar Mittal, Vice President - EHS (Corporate), C-89 to C-95 MIDC Area, MIDC Mahad, Dist. Raigad (Maharastra) - 457002, Prior Environment Clearance for Proposed expansion project for manufacturing of API at village - Sejavta, Tehsil & Dist. Ratlam, (MP)</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed expansion project for manufacturing of API at village - Sejavta, Tehsil & Dist. Ratlam, (MP). Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Dyes & Dye Intermediates) Project.

The case was presented by the PP Shri Manoj Kumar Mittal, Vice President - EHS (Corporate) from M/s. Ipca Laboratories Ltd, and their consultant and during presentation following details were provided.

- M/s. Ipca Laboratories Ltd (Ipca), is large scale manufacturing facility located at Village – Sejavta, Tehsil & Dist. Ratlam, (MP).
- Total production capacity after expansion of API will be 5078 TPA (Existing 3222 TPA & Additional proposed: 1856 TPA).
- The project occupies a plot Area of 45.94 Ha. (459400 m2) of land. The total cost of the project after expansion will be 995.00 Cr. (Existing: 702.20 Cr. & Additional proposed: 292.80 Cr.).
- The major facilities are Boilers, Thermo packs, MEEs, MVRE, Effluent Treatment Plant (ETP) and R.O Plant, Reactors, Cooling Towers etc. Facilities like additional manufacturing building & greenbelt/plantation will also be developed as per plan/requirement. The treated water will be used for cooling towers, boilers, floor washing and gardening/greenbelt etc.
- Total raw water requirement for the proposed expansion project willbe2570 KLD fresh and after recycling of 1380KLD, the fresh water requirement will be 1190 KLD. The water will be source from Municipal Authority, Ratlam & CGWA.
- Solid waste generated during the manufacturing process and wastewater treatment process is mainly sludge and will be disposed at authorized TSDF facility / Preprocessing / co-processing at Cement Plants or Incinerated in house, as per Hazardous and Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2008(Amendment2016). M/s Ipca Laboratories already taken

authorization Under Hazardous Waste (Management, Handling & Transboundary Movement), Rules. Certain category of HW will be sold to recycler / actual users.

- Power will be sourced from existing line of 'MPPK Vidyut Vitaran Company Limited Ujjain Region'. The total requirement after expansion connected load 33894 KW & Operational load 11660 KW. In case of power failure, D.G. of 1000 KVA (3 Nos.), 1010 KVA (2 Nos.), 395 KVA (1 No.), 260 KVA (1 No.) and 1500 KVA (1 No.) will be use as a back up power source.
- The total capital cost for environmental measures will be Rs. 173.443 Cr. (capital cost) (including CER cost of Rs. 2.196 Cr.) is allocated for environmental management systems and the annual recurring cost for the same will be Rs. 43.9475 Cr./A.

Executive Summary of Project:

Ipca Laboratories limited (Ipca) has emerged as one of India's top exporters of APIs with nearly 25% of the turnover coming from APIs. Regulated markets like the USA, Canada, Europe and Australia account for 75% of our API exports. Ipca is one of the world's largest manufacturers of APIs - Atenolol (anti-hypertensive), Chloroquine Phosphate (anti-malarial), Furosemide (diuretic), Hydroxychloroquine Sulphate (NSAID), Metoprolol Succinate (anti-hypertensive), Metoprolol Tartrate (anti-hypertensive) and Pyrantel Salts (anthelmintic) - besides being one of the largest suppliers of these APIs worldwide. For over 20 years, Ipca has been playing a lead role in the Indian APIs market, both in the anti-malarial and anti-hypertensive therapeutic segments. Ipca is the first manufacturer in India for APIs like Atenolol, Hydroxycholoquine Sulphate, Morantel Citrate, Pyrantel Pamoate and Zaltoprofen. Our domestic pharmaceutical customers include pharmaceutical majors like Abbott, Astra Zeneca, Bayer, Cipla, Dr. Reddy's, Merck, Pfizer, Ranbaxy, and Wockhardt. Ipca's APIs and Formulations produced at world class manufacturing facilities are approved by leading drug regulatory authorities including, UK-Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), South Africa-Medicines Control Council (MCC), Brazil-Brazilian National Health Vigilance Agency (ANVISA) and Australia-Therapeutic Goods Administration (TGA). With operations in over 120 countries, exports account for over 52% of the company's income. A favorable market demand for the pharmaceutical products in the country and a good export

potential was the chief impetus for Ipca Laboratories Ltd. to set up a fully-fledged manufacturing complex with all off sites, utilities & auxiliaries at Village Sejavta in Ratlam district of Madhya Pradesh & it has been successfully operating since 1984. After establishment in 1984, Ipca obtained EC for expansion in 2008 and subsequently in 2015 from Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Impact Assessment Division). Certified compliance report for the recent EC conditions from RO, MoEF&CC dated 17th September 2018 is available and attached as Annexure. Ipca is now proposing further expansion of existing API products with additions of new API products. Proposed expansion will be at existing site located at village Sejavta in Ratlam district of Madhya Pradesh which is already converted for industrial purpose. For proposed expansion additional land is acquired which located just adjacent of existing area & same land is already converted for industrial use. Existing unit is for manufacturing of Synthetic API, Formulations of Tablets, Injections, Liquids Orals, Dry Syrup, Ointment, Production of Steroid & Hormonal products and R&D Products. Copy of valid consent to operate (CTO) is attached as Annexure. Now, unit is going for expansion exclusively for the Synthetic API and production of all other products remains as per current valid CTO. Executive Summary of Ipca Laboratories Ltd. Village Sejavta, Tehsil & District Ratlam, Madhya Pradesh. Total capacity of the unit after proposed expansion will be API products 5078 TPA. As per the EIA Notification S.O. 1533 dated 14th September 2006, proposed activity is covered under Synthetic Organic Chemicals Industry 5(f), and needs prior environmental clearance for expansion. With reference to the vide MoEF&CC Notification S.O.2859 (E) dated 16th July 2021, the proposed activity comes under activity 5(f) API under B2 category. As per EIA notification 2006 Public Hearing is exempted for B2 category projects, hence, though the project is located outside the notified industrial public hearing is not applicable.

Salient Features of the Project:

Sr. No	Parameters	Description
1.	Category as per EIA Notification	5 (f) B-2
2.	Latitude	23^0 23'3.12"N – 23^0 23'39.32"N
3.	Longitude	75^0 3'5.81"E – 75^0 4'5.81"E
4.	Total Production Capacity	Existing capacity*: Synthetic Drug API: 3222 TPA, Additional proposed capacity: Synthetic Drug API: 1856 TPA, Total capacity: Synthetic Drug API: 5078 TPA,

Sr. No	Parameters	Description
5.	Total Area	Existing: 40.47 Ha. (404700 m^2), Additional proposed: 5.47 Ha. (54700 m^2), Total: 45.94 Ha. (459400 m^2),
6.	Green Belt Area	15.1602 Ha (151602 m^2) (33% of total plot area).
7.	Water Requirement	Existing: 1475 CMD, Additional proposed: 1095 CMD, Total: 2570 CMD.
8.	Effluent Quantity (Trade + Domestic)	Existing: Trade: 620 CMD & Domestic: 140 CMD, Additional proposed: Trade: 589 CMD & Domestic: 00 CMD, Total: Trade: 1209 CMD & Domestic: 140 CMD,
9.	Trade Effluent Treatment	Trade effluent will be segregated into high TDS and low TDS streams. High COD/TDS stream from process (100 CMD) will be treated in primary treatment first and then passed through Stripper for solvent recovery. Then it will be passed Multiple Effect Evaporator (MEE-1, existing) followed by Agitated Thin Film Dryer. MEE condensate (120 CMD: 100 CMD MEE treated + 20 CMD live steam condensate) will be further treated in full-fledged ETP-2 (Proposed). Low TDS stream (1109 CMD) will be further separate out.258 CMD from process 221 CMD form floor wash, etc. and 80 CMD from boiler blow downs totaling to 559 CMD will be treated in conventional ETP (proposed) along with MEE 1 condensate. Total effluent going to ETP (proposed) will be 679 CMD. Treatedeffluent will be fed to existing RO1 followed by RO2. RO3 will be stand by. Permeate (475 CMD) will be recycled and reused Rejects (204 CMD) from RO will be fed to existing MVRE. Remaining 550 CMD Lean streams (low TDS) coming from cooling tower blow downs (305 CMD), DM reject (195 CMD) & stream from formulation (50 CMD) will be fed to ETP (Existing) comprising of primary and secondary. Then it will be fed to RO4 (Proposed). RO permeate (413 CMD) will be recycled and reused and reject (137 CMD) will be fed to MVRE along with rejects from RO1 and 2. Condensate from MVRE (222 CMD) will be recycled and reused and concentrate (119 CMD) will be fed to MEE2 (proposed). Condensate (130 CMD) from MEE 2 (proposed) will be recycled and reused. Unit will be complete ZLD unit. Total Recycled water will be 1240 CMD.
10.	Domestic waste water treatment	Domestic waste water will be treated in existing STP of capacity 140 CMD.
11.	Fuel requirement full load	Equipment & Fuel / Existing Fuel Quantity / Additional Proposed Fuel Quantity / Total Fuel Quantity

Sr. No	Parameters	Description				
		For	Boilers	Petroleum Cock / Coal: 1T/hr., (For 6 TPH boiler – 1 number), Furnace Oil: 450 Lit/hr., (For 6 TPH boiler – 1 number), Coal: 1 T/hr. (For 6 TPH boiler – 1 number), Coal: 1.20 T/hr. (For 8 TPH boiler – 1 number), Petroleum Cock: 1.10 T/hr., (For 8 TPH boiler – 1 number).	Coal: 10 T/hr. (For 20 TPH boiler - 1 number & 30 TPH Boiler - 1 number),	Furnace Oil: 450 Lit/hr., (For 6 TPH boiler – 1 number), Coal: 13.2 T/hr., (For 6 TPH boiler – 2 numbers, 8 TPH boiler, 20 TPH boiler & 30 TPH boiler – 1 number each), Petroleum Cock: 1.10 T/hr., (For 6 TPH boiler – 1 number &8 TPH boiler – 1 number).
		For	Thermopack	LDO: 125 Litrs/hr., (For 4 Lac kcal/hr., 2 Lac kcal/hr. 2 Lac kcal/hr. & 1 Lac kcal/hr.)	--	LDO: 125 Litrs/hr., (For 4 Lac kcal/hr., 2 Lac kcal/hr. 2 Lac kcal/hr. & 1 Lac kcal/hr.)
		For	DG sets HSD	655 Litrs/hr. (For DG Sets.: 1000 KVA - 3 numbers, 1010 KVA - 2 numbers, 395 KVA - 1 number & 260 KVA - 1 number)	355 Litrs./hr., (For DG Set: 1500 KVA - 1 number)	1010 Litrs. /hr. (For DG Sets.: 1000 KVA - 3 numbers, 1010 KVA - 2 numbers, 395 KVA - 1 number, 260 KVA - 1 number, 1500 KVA - 1 number)
12.	Power requirement	Existing: Connected Load: 28902 KW, Operational Load: 10000 KW, Additional proposed: Connected Load: 4992 KW, Operational Load: 1660 KW, Total: Connected Load: 33894 KW, Operational Load: 11660 KW, Source: MPPK Vidyut Vitaran Company Limited Ujjain Region.				
13.	Dispersion of boiler emission for boiler	Existing: Stack Height- Boiler 6 TPH (3 numbers), 8 TPH (2 numbers): Existing 30 m. stack height to each boilers are provided, Thermopack: 4 Lack cal/hr., 2 Lack cal/hr., 2 Lack cal/hr., 1 Lack cal/hr.				

Sr. No	Parameters	Description
		(stand by). Existing 23 m. common stack height. Additional proposed: Stack Height- For boiler 20 TPH & 30 TPH: Stack height of 50 m will be provided to each boilers,Earlier stack height provided 30 m each however after air modelling study it has been revised to 50 m. for proper dispersion of pollutants.
14.	Dispersion of emission DG Sets	Existing: Total D.G Sets X 7 Nos. 3 Nos.: 1000 KVA, Common stack height: 30 m along with acoustic enclosure is provided, 2 Nos.: 1010 KVA, Common stack height: 30 m along with acoustic enclosure is provided, 1 No.: 395 KVA, Stack Height: 4 malong with acoustic enclosure is provided, 1 No.: 260 KVA, Stack Height: 3.5 m along with acoustic enclosure is provided, Additional proposed: D.G Set X 1 No.: 1500 KVA Stack Height: 30 m along with acoustic enclosure will be provided,
15.	Work Force	Existing: 2650 Nos. Additional proposed: 00 Nos. Total: 2650 Nos.
16.	Capital Cost the project	Existing: 702.20 Cr., Additional proposed: 292.80 Cr. Total capital Cost: 995.00 Cr.
17.	Corporate Environmental Responsibility (CER)	CER Cost: Rs.2.196 Cr(0.75 % of the expansion cost i.e. 292.80 Cr) (As per conditions stipulated in O.M issued by MoEF&CC O.M No. 22-65/2017-IA.III dated 25th Feb. 2021, CER will be a part of EMP).

After presentation, PP was asked to submit of following details:

1. Water Analysis report w.r.t. BOD parameter (inlet & outlet of ETP).
2. Furnish details of CO_2 carbon emission, quantification of proposed boilers & DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print of the industrial activity.
3. MSDS of all 18 new products handling in the industry including their solvents.
4. Quantify the worst case scenario wrt to any industrial accidents like spill of HCL acid.
5. Revised plantation species as suggested by the committee.
6. Revised CER activities with their physical & financial target as habitat development in the Ralamandal WLS, Indore and in the Van Vihar National Park, Bhopal with additional financial budgetary provision of 20.0

lakhs and 05.0 lakhs respectively (to be deposited within a month after getting E.C.) before 31st March 2022 apart from other activities as suggested during presentation by the committee.

PP has presented reply of the queries raised in 542nd meeting. The query reply was presented by the PP and after deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for proposed expansion project for manufacturing of API at Village Sejavta, Tehsil & District Ratlam, Madhya Pradesh proposed by M/s Ipca Laboratories Ltd., Land Area: 45.94 Ha., Proposed Total Capacity after expansion for API: 5078 TPA under Cat. 5(f) Synthetic Organic Chemicals Industry (Bulk Drug), B2 Category. Project subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA),1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act,1986.
2. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (if applicable). The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
3. Storage of raw materials, coal etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
4. The DG set (1500 KVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
5. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608 (E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be

followed.

6. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
2. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.
3. The High COD/TDS process effluent and RO Reject will be treated through Stripper, MEE, ATFD. The MEE-1 condensates will be send to ETP for further treatment and MEE-2 condensate shall be recycled / reutilized back in plant utility .MEE bottom will be sent to TSDF site
4. The Low COD/TDS effluent along with blowdown from utility and washing activity will be treated in an on-site ETP followed by MVRE, RO& MEE. **The t**reated effluent will be reused/recycled.
5. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
6. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
7. Total fresh water requirement shall not exceed 2570KLD.
8. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
9. The Company shall harvest rain water from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the groundwater and utilize the same for different industrial operations within the plant.
10. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Acoustic enclosure shall be provided to DG (1500 KVA) set for controlling the noise pollution.
2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75dB(A) during day time and 70dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
2. The total power requirements for project will be 33894 KW. The power will be supplied by MPPK Vidyut Vitaran Company Limited Ujjain Region.

(F) Waste management

1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
2. As proposed, 92-95% solvent recovery shall be achieved and recovered solvent shall be reused in the process.
3. Hazardous wastes such as spent solvents, organic incinerable wastes/residues, used filter bags, packaging materials, rejected/expired raw materials and off specification/ rejected finished products from the manufacturing plants shall be directly sent to TSDF, Pithampur/ Recyclers / Pre or coprocessors
4. The Fly ash generated from boilers shall be stored in Covered shed and disposed of through cement manufacturers or brick manufacturers by bulkers / closed containers and should comply with Fly Ash Utilization Notification, 1999 and as amended subsequently.
5. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
6. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
7. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
8. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is atleast150mm above the maximum flood level.
9. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
10. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
11. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
12. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
13. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
14. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
15. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge,

process inorganic& evaporation salt shall be disposed off to the TSDF/ Preprocessor.

16. The company shall undertake waste minimization measures as below:

a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
c. Use of automated filling to minimize spillage.
d. Use of Close Feed system into batch reactors.
e. Venting equipment through vapour recovery system.
f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce waste water generation.

(G) Green Belt

1. The additional green belt of 5-10 m width shall be developed 4200 sq. meter within and periphery of plant (5000 nos.), along road sides and at open spaces at existing green belt etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guidelines in consultation with the State Forest Department.
2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2.5 feet height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature and species as suggested by the committee. As proposed 5000 nos. of plants shall be planted green belt mainly along the periphery of new plot and at open spaces at existing green belt at a distance of 2 m x 2 m to achieve 2500 Nos of trees/ Ha. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Firefighting system shall be as per the norms.
3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for

raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP & Corporate Environment Responsibility

1. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/ violation of the environmental/forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements deviation/violationoftheenvironmental/forest/wildlifenorms/conditionsandorshareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
2. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
3. The proposed EMP cost is Rs. 173.443Cr.as capital and 43.9475 Cr./year as recurring cost.
4. The proposed CER cost will be 2.196 Cr. which will be incurred on skill training development programme in Amletha Village, Provision of drinking water, waste management and health center facility to Sejavta Village, Provision of emergency medical service and facility in Sejavta Village, Provision of Solar system in surrounding villages, Greenbelt plantations in nearby areas like school, Grampanchyat area's and allotment of Rs. 5 Lacs to Anganwadi of tribal area of district Ratlam as a part of CER fund only.
5. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
6. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

(J) Miscellaneous

1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC &SEIAA.
2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing (if applicable) and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention

&Control of Pollution)Act,1974,theAir(Prevention&ControlofPollution)Act,1981,the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

16. दिनांक 15/1/22 को SEIAA द्वारा SEIAA एवम् SEAC की संयुक्त बैठक

दिनांक 15/2/22 को SEIAA द्वारा SEIAA एवम् SEAC की एक संयुक्त बैठक का आयोजन म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 108/1033/2021/32–3 भोपाल दिनांक 31/1/2022 के द्वारा जारी निर्देशो के पालनार्थ किया गया था । बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :–

1. श्री अरूण भट्ट, अध्यक्ष, एस.ई.आइ.ए.ए., म.प्र. ।
2. श्री पी.सी. दुबे, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी., म.प्र. ।
3. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, एस.ई.आइ.ए.ए., म.प्र. ।
4. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी., म.प्र. ।
5. श्री अनिल शर्मा, सदस्य, एस.ई.आइ.ए.ए., म.प्र. ।
6. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, एस.ई.ए.सी., म.प्र. ।
7. श्री अलोक नायक, समन्वयक, एस.ई.आइ.ए.ए., म.प्र. ।
7. श्री अभय कुमार सक्सेना, समन्वयक, एस.ई.ए.सी., म.प्र. ।

बैठक में अध्यक्ष, एसईएसी ने अवगत कराया कि म.प्र. शासन पत्र क्र. 108/1033/2021/32–3 भोपाल दिनांक 31/1/2022 के द्वारा जारी निर्देशो के अनुरूप ही एसईएसी द्वारा कार्य संपादित किये जा रहे है तथा बिंदु क्रमांक 06 के पालनार्थ वर्तमान में संबंधित जानकारी शासन स्तर के कार्यालयो से प्राप्त करने बावत् पत्राचार एसईएसी द्वारा किया जा रहा है ।

बी–1 और बी–2 के प्रकरणा में निर्धारित समय सीमा के अनुरूप ही कार्य संपादित किये जा रहे है तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटान हेतु यथा संभव प्रयास कर कार्यावाही की जा रही है, जिसके फलस्वरूप फरवरी–22 माह में एसईएसी की लगभग 10 बैठके आयोजित है जिसमें से आज दिनांक तक 04 बैठक आयोजित की जा चुकी है तथा लगभग 06 बैठक दिनांक 16/2/22 से 18/2/22 तक तथा 22/2/22 से 24/2/22 तक की जाना प्रस्तावित है, जिसका एजेण्डा अपलोड किया जा चुका है ।

ऐसे प्रकरण जहॉ सेक द्वारा जानकारी चाही गई है तथा वह जानकारी यदि 30 दिनों तक प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट कर सिया को भेजा जा रहा है ।

अध्यक्ष, एसईएसी ने अवगत कराया कि प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण एकल प्रमाण–पत्र में प्राप्त जानकारी तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोडेड गूगल मेप के आधार पर किया जाता है तथा पर्यावरण संवेदनशील कारकों को ध्यान में रखकर संबंधित प्रकरणो में अनुशंसा एसईआइएए को प्रेषित की जाती हैं । सेक द्वारा सभी बैठकें ऑनलाईन आयोजित की जा रही है जिसमें परियोजना प्रस्तावक व उसके पर्यावरण सलाहकार अपना प्रस्तुतीकरण ऑनलाईन दे सकते हैं ।

चर्चा के द्वारा एसईआइएए को अवगत कराया गया कि एसईआइएए की बैठक 694वीं बैठक दिनांक 26/11/21 में लिए गए निर्णय के अनुसार कच्चे रोड से 50 मीटर की दूरी छोडने के निर्देशों के कारण प्रोजेक्ट परीक्षण में कठिनाई आ रही है क्योकि सभी खदाने म.प्र. राज्य के एमएमआर, 1996 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुरूप स्वीकृत की गई है जिसमे कच्चे रोड़ में दूरी 10 मीटर, पक्के रोड़ में दूरी 50 मीटर तथा एनएच/एसएच से दूरी 100 मीटर उल्लेखित है । अतः प्रस्तावित है कि वर्तमान में खदान से प्रतिबंधित दूरी म.प्र. राज्य के एमएमआर, 1996 में उल्लेखित प्रावधानो के अनुरूप ही लागू की जावे । मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 314/2019 में जारी आदेश दिनांक 21/7/20 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही एवं निर्देश जारी करने बावत् प्रकरण राज्य शासन के माध्यम से संबंधित खनिज विभाग भेजे जाने का अनुरोध है ।

17. **<u>प्रकरण क्रमांक 8751/2021 – मेसर्स संभवी एसोसिएट्स, पन्ना</u>**

यह प्रकरण स्टोन माइनिंग से संबंधित है जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा 525वीं सेक बैठक दिनांक 10/11/21 के माध्यम से सिया को प्रेषित की जा चुकी है । श्री प्रियांश चौबे, भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 07/2/22 के माध्यम से इस प्रकरण में शिकायत प्रेषित की है जो आगामी कार्यवाही हेतु सिया की अग्रेषित है ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

549वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 15 फरवरी 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets

(separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.

16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain

them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.

17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
    - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

35. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
36. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
37. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
38. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.